प्रकाशित: 02 फरवरी 2019 को ईचर्चा.इन पर प्रकाशित-

विपक्ष के लिए 'उबला आलू' बन गले में अटक गया है अंतरिम बजट!

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री कब वित्तीय घाटे की बात करने लगें और कब देश के गरीबों की चिन्ता में दुबरा जाएं, समझ पाना बहुत कठिन होता है और ठीक इसी स्थिति में इस समय भारतीय विपक्ष है। कल तक जिस विपक्ष को सत्ता में आने पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करना देश की सारी समस्याओं का समूल नाश करने जैसा दिख रहा था, आज अंतरिम बजट के तुरन्त बाद से विपक्ष को किसानों के खाते में सीधे जाने वाली रकम भी जुमला सुनाई दे रही है। बेहतर होगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव जुमलेबाजी की परीक्षा ही हो जाए।

इस बात के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को बधाई दी जानी चाहिए कि जबरदस्त दबाव के बावजूद किसान कर्जमाफी जैसे जुमलेबाजी की तरफ सरकार नहीं गई और किसानों को मदद करके मजबूत करने के रास्ते पर सरकार आगे बढ़ी है। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो बहुत साफ था कि देश के लोगों को विकास की बड़ी उम्मीद थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग हर मोर्च पर तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बाद देश में बुनियादी ढांचे की तरक्की थमती सी दिखने लगी थी।

यूपीए 2 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से भी कम हो गई थी। अब देश में प्रतिदिन 27

किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि प्रतिदिन 16 किलोमीटर, प्रतिमाह 480 किलोमीटर और प्रतिवर्ष करीब 6000 किलोमीटर ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनने को आसानी से समझने के लिए बस जीवन में एक बार ऐसी यात्रा कीजिए, जहां सड़क से सम्पर्क नहीं है। इतने भर से आपको समझा आएगा कि देश में प्रतिदिन 16 किलोमीटर ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर सरकार क्या कर रही है। सिर्फ 16 किलोमीटर ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से देश की तरक्की की रफ्तार कितनी बढ़ी या फिर कितने लोगों को रोजगार मिला, इतना भर सही तस्वीर नहीं पेश करेगा।

दरअसल, सड़कों का पहुंचना, देश के विकास और लोगों के जीवनस्तर में बेहतरी की मूल शर्त है। इसके बाद ही विकास की दूसरी गतिविधियां शुरू होती हैं। इस बात से नरेंद्र मोदी सरकार में 16 किलोमीटर प्रतिदिन ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनने को समझा जा सकता है। जितने शहरों-गांवों के नजदीक से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेंगे, वहां के लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया में शामिल होना उतना आसान होता जाता है।

और, सिर्फ सड़कों का तेज निर्माण ही नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं है। सड़कों के साथ, रेलवे, हवाई अड्डे और जल परिवहन में भी इस सरकार ने तेजी से विकास किया है, जिसकी चर्चा कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में की, लेकिन पिछले कुछ समय से विपक्ष ने देश में एक नई बहस शुरू कर दी थी कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लगातार इस आरोप को दोहराने से और वामपंथी दलों के किसान संगठनों के दिल्ली, मुम्बई में किए गए प्रदर्शनों ने इस पर मोदी सरकार की चिन्ता बढ़ा दी थी। किसान, मजदूर और

मध्यम वर्ग पूछने लगा था कि मुझे क्या मिला? और इसी मुझे क्या मिला का जवाब इस सलीके से पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट के जरिये दिया है कि विपक्ष के लिए इस पर प्रतिक्रिया देना उबले आलू का गले में अंटकने जैसा हो गया है। अब न उगला जा रहा है और न निगला जा रहा है।

कुछ दिन पहले तक किसानों, मध्यम वर्ग की चिन्ता में दुबराए जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे खाते में सालाना 6000 रुपये मिलने को भी 17 रुपये प्रतिदिन जोड़कर किसानों का अपमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आखिरी जुमला बजट बताने वाले नेताओं में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जरा हटके बयान दिया है। उन्होंने कहाकि खाद की बोरियों में से चुराए गए रुपये को इस बजट से लौटा रही है केंद्र सरकार।

विपक्ष के पास सहूलियत होती है कि वादों से जनता को लुभा सकें और सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वित्तीय अनुशासन के साथ वादों को हकीकत में बदलकर दिखाएं। अब राहुल गांधी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जुमलेबाजी कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वित्तीय अनुशासन तोड़े देश के 12 करोड़ किसान परिवारों के खाते में सीधे 6000 रुपये सालाना देकर बढ़त हासिल कर ली। हर 4 महीने पर 2000 रुपये देने के लिहाज से ही सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 से इसे लागू किया है। बुवाई, सिंचाई के समय किसान को 2000 रुपये नकद मिलने का मतलब किसानों को ही समझ आ सकता है, दिल्ली में बैठकर चुनावी जुमलेबाजी करने वालों को यह बात शायद ही समझ आए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अपमानित करने की कोशिश करके राहुल गांधी पांव कुल्हाड़ी पर रख रहे हैं। वैसे तो किसान के लिए इस सरकार ने क्या किया है, विस्तार से एमएस स्वामीनाथन ने खुद लिखकर बताया है। स्वामीनाथन कहते हैं कि पहली सरकार है जिसने तुरन्त राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को लागू करना शुरू किया, जिससे किसानों को मजबूत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के साथ दूसरी योजना उसी राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों का हिस्सा है, जिसे किसान आसानी से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तौर पर समझता है। अब किसान को मुझे क्या मिला, का जवाब आसान भाषा में इस अंतरिम बजट ने दे दिया है।

किसानों की ही तरह मध्यम वर्ग को भी लगातार विपक्ष यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्या मिला। इस सरकार ने आपको सीधे कुछ नहीं दिया। हालांकि, मध्यम वर्ग को बेहतर जीवनस्तर के लिए अच्छी सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे की सुविधा सबसे बड़ी जरूरत होती है और उस पर इस सरकार के काम की आलोचना लगभग असम्भव सी दिखती है, लेकिन टैक्स छूट न मिलने से पिछले 2 बजट से नौकरीपेशा मध्यम वर्ग निराश हो रहा था और उसे विपक्ष की बात ठीक लगने लगी थी कि आपको क्या मिला।

अच्छी सड़क, बिजली, रेलवे, हवाई परिवहन की सुविधा तो सबके लिए है। हालांकि, बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरीपेशा, मध्यमर्ग की ईमानदार टैक्सपेयर के तौर पर पहचान करके सम्मान बढ़ाते थे, लेकिन मुझे क्या मिला वाला सवाल नौकरीपेशा, मध्यम वर्ग के मन में बड़ा होता जा रहा था। अब 5 लाख रुपये की आमदनी पूरी तरह से करमुक्त

कर देने के एलान से नौकरीपेशा, मध्यम वर्ग को भी मुझे क्या मिला, का जवाब मिल गया है।

पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते बताया कि निवेश और दूसरी छूट के साथ 6.5 लाख तक की कमाई करने वाले को टैक्स नहीं भरना होगा। और, यह बात समझना जरूरी है कि 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई वाले टैक्स भरने वालों का करीब 90 प्रतिशत हैं। करीब 3 करोड़ लोगों को मुझे क्या मिला का जवाब मिल जाने का मतलब विपक्ष को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।

किसान और मध्यम वर्ग के अलावा असंगठित क्षेत्र का मजदूर भी यह सवाल लगातार पूछने लगा था कि मुझे क्या मिला। इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी बजट में दिया गया है। अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों – रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शाचालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार आदि- को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये महीने की पेंशन की योजना लागू की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना के तहत 18 साल के श्रमिक को हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा और इतनी ही रकम सरकार भी हर महीने देगी।

अंतरिम बजट पेश करते पीयूष गोयल ने बताया कि न्यनूतम मजदूरी 10000 से बढ़ाकर 21000 रुपये इसी सरकार के दौरान की गई है और बोनस भी 3000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी गई है। किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को मुझे क्या मिला का जवाब मिल गया है। और एक सबसे जरूरी बात जो कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताई, उसके लिए उन्हें विशेष बधाई। अब देश की हर रेलवे क्रॉसिंग

सुरक्षित है। रेलवे क्रॉसिंग खुली होने से होने वाली दुर्घटना अब नहीं होगी। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं।